

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

Q.1) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है

- वित्त मंत्री
- आरबीआई गवर्नर
- वित्त सचिव
- प्रधान मंत्री

Q.1) Solution (a)

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- एफएसडीसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले क्षेत्रक नियामकों (sectoral regulators) का सर्वोच्च निकाय है।
- सभी वित्तीय क्षेत्रक नियामक प्राधिकरणों जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, PFRDA आदि के प्रमुख, FSDC के सदस्य होते हैं।
- राज्य मंत्री, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, परिषद में नए जोड़े गए हैं।

Q.2) भारत के कर संग्रह के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।
- निगम कर का हिस्सा वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से अधिक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।	निगम कर की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से कम है

Q.3) छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं के माध्यम से संचित धन कहाँ रखा जाता है

- भारतीय समेकित कोष
- भारतीय सार्वजनिक खाते
- भारतीय आकस्मिकता निधि
- संबंधित राज्य के समेकित निधि

Q.3) Solution (b)

- भारतीय सार्वजनिक खाता संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित किया गया है।

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

- भारत के समेकित कोष में शामिल धन के अलावा प्राप्त सभी सार्वजनिक धन भारत के सार्वजनिक खाते में आयोजित किए जाते हैं।
- इस खाते में मुख्य रूप से छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं आदि के माध्यम से धन संचित किया जाता है।
- सरकार केवल इन फंडों की संरक्षक होती है। इसे या तो परिपक्वता तिथि पर या जब भी लोगों द्वारा दावा किया जाता है, चुकाना पड़ता है।

Q.4) निम्नलिखित में से किसे सरकार के गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (Non-Tax Revenue receipts) के रूप में माना जाता है

1. स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
2. मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन से लाभ।
3. निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से लाभांश।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती हैं।	मुद्रा, सिक्का और टकसाल अन्य गैर-कर प्राप्तियों की वित्तीय सेवाओं के तहत आते हैं।	गैर-कर राजस्व - लाभांश निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से आय है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियां

- ब्याज प्राप्तियां
- लाभांश और लाभ
- मुद्रा, सिक्का, टकसाल
- सामाजिक सेवा
- सहायता अंशदान में अनुदान
- आर्थिक सेवाएँ

पूंजीगत प्राप्तियां

- स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
- दूसरों को दिए गए ऋणों की वसूली
- सरकार द्वारा लिया गया उधार

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

Q.5) स्थायी संपत्ति बनाने तथा समय-समय पर आय अर्जित करने वाले व्यय को कहा जाता है

- a) राजस्व व्यय
- b) परिसंपत्ति व्यय
- c) पूंजीगत व्यय
- d) प्राथमिक व्यय

Q.5) Solution (c)

- पूंजीगत व्यय, वे व्यय हैं
 - जो स्थायी संपत्ति बनाते हैं और समय-समय पर आय देते हैं।
 - राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में दिए जाते हैं।
- यह दो तरफा भुगतान होते हैं। इसका मतलब है कि व्यय किए गए धन को आवधिक आय और / या बनाई गई संपत्ति के निपटान के माध्यम से वापस प्राप्त किया जा सकता है।

Q.6) राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) को संदर्भित करता है

- a) उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
- b) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
- c) ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.6) Solution (a)

राजकोषीय घाटा	उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
प्राथमिक घाटा	ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा एक आर्थिक क्रिया है, जहां सरकार का कुल व्यय उत्पन्न राजस्व से अधिक होती है।
- राजकोषीय घाटा सरकार को सभी स्रोतों से कुल उधार आवश्यकताओं के बारे में संकेत देता है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है।
2. कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

Q.7) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है। कर प्लवनशीलता = कर राजस्व में परिवर्तन / सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात में परिवर्तन का अनुपात।	कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

Q.8) वस्तु एवं सेवा कर (GST) निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?

1. एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं।
2. एक नए भवन के निर्माण में एक बिल्डर द्वारा सेवाएं।
3. दूध बूथों और किराने की दुकानों में उपलब्ध स्वादिष्ट दूध (flavoured milk)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	सत्य	सत्य
एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, कर्मचारी कमाए गए वेतन पर आयकर का भुगतान करेगा।	एक नए भवन का निर्माण जीएसटी (कार्य अनुबंध होने के नाते) के अधीन है।	गैर-स्वाद वाले दूध और दूध पाउडर को जीएसटी से छूट दी गई है लेकिन स्वादिष्ट दूध पर 12% स्लैब के तहत जीएसटी कर लगाया जाता है।

Q.9) विनिवेश (Disinvestment) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती है।
2. निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण रणनीतिक विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती है। अर्जित निधि का उपयोग चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। यह कोष भारत के समेकित कोष से बाहर रखा गया है।	रणनीतिक विनिवेश किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण है। साधारण विनिवेश के विपरीत, रणनीतिक विनिवेश का अर्थ एक तरह का निजीकरण है।

Q.10) निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एफआरबीएम अधिनियम समीक्षा समिति की सिफारिशें हैं?

- सरकार को सलाह देने के लिए राजकोषीय परिषद का गठन।
- राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात (Public debt to GDP ratio) को एक मध्यम अवधि के उद्घोषक के रूप में माना जाता है।
- एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.10) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
‘राजकोषीय परिषद’ की स्थापना, एक स्वतंत्र निकाय, जो किसी भी वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय घोषणाओं की निगरानी का काम करेगा।	राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात को एक मध्यम अवधि के एंकर के रूप में माना जाता है। केंद्र सरकार के लिए 38.7% का ऋण-से-जीडीपी अनुपात है, यह राज्य सरकारों के लिए 20% है	एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

Q.11) अग्रिम मूल्य समझौता (Advance pricing Agreement) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है।
- इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कई संस्थाओं के साथ एक एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।	इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह बेहतर अनुपालन के साथ-साथ बेहतर कर निगरानी दोनों में मदद करता है।

Q.12) निम्नलिखित में से कौन 15 वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें (terms of reference) हैं

- राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना।
- बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन।
- जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.12) Solution (d)

15 वां वित्त आयोग - संदर्भ की शर्तें (Terms of reference)

- जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास
- जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
- बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना
- स्थानीय निकायों को अनुदान
- स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति
- लोकलुभावन उपायों पर नियंत्रण।

Q.13) वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
एफआईआई राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। 3 आयाम - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता	यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

Q.14) आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) परियोजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह परियोजना बीईपीएस से निपटने के लिए ओईसीडी का एक परिणाम है।
2. भारत ने कर चोरी की जाँच पर ओईसीडी की परियोजना को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.14) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) से निपटने के लिए यह परियोजना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) / G20 का एक परिणाम है।	भारत इस परियोजना का संस्थापक सदस्य था। भारत ने 2016 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।

Q.15) निम्न में से किसे पिगोवियन कर (Pigovian tax) माना जाता है

- a) अमीरों पर संपत्ति कर
- b) कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण
- c) विलासिता की वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.15) Solution (b)

पिगोवियन कर (Pigovian tax)

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

- एक पिगोवियन (Pigouvian) कर एक ऐसा कर है, जिसका मूल्यांकन निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए किया जाता है, जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं।
- इनमें पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव तथा बाहरी, नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य दुष्प्रभाव शामिल होते हैं।
- पिगोवियन कर का अर्थ उन गतिविधियों को हतोत्साहित करना है जो उत्पादन की लागत को तीसरे पक्ष और समाज पर एक संपूर्ण के रूप में लगाती हैं।

Q.16) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तहत एक समिति है।
2. बीसीबीएस द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के तहत एक समिति है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) बैंकों के विवेकपूर्ण नियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक-सेटर है।	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

Q.17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लोकसभा में बिना किसी चर्चा के लेखानुदान (Vote on account) पारित किया जाता है
2. पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित होता है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है
3. चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (d)

लेखानुदान अनुदान देने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक सरकार को कार्यप्रणाली संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम रूप में एक अनुदान है। यह सरकार को कम समय के लिए या एक पूर्ण-बजट पारित

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

होने तक खर्च करने में सक्षम बनाता है। एक कन्वेंशन के रूप में, एक लेखानुदान को औपचारिक मामला माना जाता है और बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।

पूर्ण बजट और लेखानुदान के बीच अंतर

पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है।

लेखानुदान आम तौर पर दो महीने के लिए वैध होता है लेकिन एक पूर्ण बजट 12 महीने (एक वित्तीय वर्ष) के लिए मान्य होता है।

एक लेखानुदान प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें एक वित्त बिल के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता होती है। नियमित बजट के तहत, नए कर लगाए जा सकते हैं और पुराने समाप्त किये जा सकते हैं।

सभी व्यावहारिक अर्थों में एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट होता है लेकिन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान - अर्थात् चुनाव से ठीक पहले बनाया गया होता है। एक अंतरिम बजट खातों का एक पूरा सेट है, जिसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। लेकिन इसमें बड़े नीतिगत प्रस्ताव नहीं हो सकते हैं।

चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है।

Q.18) आभासी मुद्राओं (Virtual Currencies) पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी

- उदय कोटक समिति
- नंदन नीलेकणी समिति
- नचिकेत मोर समिति
- सुभाष चंद्र गर्ग

Q.18) Solution (d)

- आभासी मुद्राओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने की थी।
- मुख्य सिफारिशें**
 - निजी क्रिप्टो-मुद्राओं के सभी रूपों पर प्रतिबंध।
 - देश में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत को देखना।
 - डेटा संरक्षण विधेयक में प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
- केंद्र द्वारा गठित समिति ने एक मसौदा विधेयक-क्रिप्टो-मुद्रा का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के विनियमन का भी प्रस्ताव किया है।

Q.19) भारत सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। NDIAC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- NDIAC एक पेशेवर रूप से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।
- NDIAC अधिनियम NDIAC को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
NDIAC एक पेशेवर, लागत प्रभावी और समय पर ढंग से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।	NDIAC अधिनियम, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह NDIAC को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है।

- NDIAC अधिनियम ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान (ICADR) को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है।
- NDIAC मध्यस्थता का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगा जो चैंबर ऑफ़ आर्बिट्रेशन की स्थापना करेगा।
- NDIAC मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक मध्यस्थता अकादमी भी स्थापित कर सकता है।

Q.20) मानक कटौती (Standard Deduction) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह वेतनभोगी व्यक्तियों को उन खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, जो उसके या उसके रोजगार के संबंध में खर्च होंगे
2. इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है
3. इसे पहली बार बजट 2019 में प्रस्तुत किया गया था

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
अपने बजट 2018 के भाषण में, वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को वेतन आय से 40,000 रुपये की मानक कटौती प्रदान करने (पुनः प्रदान करने) का प्रस्ताव दिया था। मानक कटौती से वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने या अपने रोजगार के संबंध में होने वाले खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति मिलती है।	इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।	वर्ष 1974 में आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में आकलन वर्ष 2006-07 से इसे समाप्त कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा मानक कटौती को वापस लेने का यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

		बुनियादी छूट सीमा और धारा 80C की कटौती में बराबर वृद्धि हुई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर योग्य वेतन मानक कटौती के कारण नीचे आ जाएगा।
--	--	---

Q.21) नए पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (UPOV) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित है।
2. यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।
3. यह नए पौधों की किस्मों के प्रजनकों के लिए एक बौद्धिक संपदा अधिकार देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ग़लत है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 3

Q.21) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
UPOV को पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (UPOV Convention) द्वारा स्थापित किया गया है। कन्वेंशन नए पौधों की किस्मों के प्रजनकों को बौद्धिक संपदा अधिकार: प्रजनक का अधिकार प्रदान करके पौधों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों को आधार प्रदान करता है।	नए पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (UPOV) एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।	प्रजनक के एक प्राधिकरण द्वारा संरक्षित विविधता के मामले में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विविधता का प्रचार करना आवश्यक है। प्रजनक का अधिकार व्यक्तिगत रूप से यूपीओवी सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाता है।

Q.22) फकीम वन्यजीव अभयारण्य, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- a) अरुणाचल प्रदेश
- b) नागालैंड
- c) मणिपुर
- d) मिजोरम

Q.22) Solution (b)

- फकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा के समीप स्थित है।
- नागालैंड में सबसे लोकप्रिय पक्षी हार्नबिल फकीम वन्यजीव अभयारण्य में भी बहुतायत से पाया जाता है।

Q.23) कार्रवाई के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क (Biwako Millennium Framework for Action) किसके साथ संबंधित है

- दिव्यांगजन
- लैंगिक असमानता को कम करना
- पर्यावरणीय शरणार्थियों
- मानव तस्करी

Q.23) Solution (a)

- एशिया और प्रशांत में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, अवरोध मुक्त और अधिकारों पर आधारित समाज हेतु कार्रवाई के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क लाया गया है।
- यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए नीति दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

Q.24) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), निम्नलिखित में से किसके आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है?

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

Q.24) Solution (d)

- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था ताकि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनी जा सके।
- एनसीएलटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करता है।
- NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
- NCLAT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है -
 - दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 61 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
 - इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) धारा 202 और IBC की धारा 211 के तहत।
 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में लाए गए संशोधन के अनुसार

Q.25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- टिडु गतिविधि के जोखिमों के हॉटस्पॉट की पहचान प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा की जाती है।
- दक्षिण पश्चिम एशिया, टिडु गतिविधि के जोखिमों के तीन हॉटस्पॉटों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.25) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
टिड्डी गतिविधि के जोखिमों के हॉटस्पॉट की पहचान संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा की जाती है।	एफएओ ने वर्तमान में जोखिमकारी टिड्डे की गतिविधि के तीन हॉटस्पॉटों की पहचान की, जहां स्थिति को "बेहद खतरनाक" कहा गया है - हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम एशिया।

Q.26) के.पी. कृष्णन समिति हाल ही में समाचारों में थी। यह किससे संबंधित है

- क्रॉस-बॉर्डर इंसांल्वेंसी
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- समान पारिश्चमिक

Q.26) Solution (a)

इन्सांल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत सीमा पार इन्सांल्वेंसी प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमों और नियामक ढांचे की सिफारिश के लिए समिति का गठन किया गया था।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अब इस पैनल के संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया है, जो एक सीमा पार से आधार पर उद्यम समूह के दिवालिया होने से संबंधित पहलुओं को कवर करने के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के. पी. कृष्णन की अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया है।

यह 'उद्यम समूह दिवालिया' के लिए यूनीट्रल मॉडल लॉ (Uncitral Model Law) का अध्ययन और विश्लेषण करेगा तथा इन्सांल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 (IBC) के संदर्भ में सिफारिशें करेगा।

Q.27) 'एयर इंडिया' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

- 1991 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- इसकी स्थापना जे. आर. डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी।
- (a) और (b) दोनों
- न तो (a) और न ही (b)

Q.27) Solution (b)

एयरलाइन की स्थापना जे.आर. डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी।

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत में नियमित वाणिज्यिक सेवा बहाल हो गई थी तथा टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया नाम से 29 जुलाई 1946 को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई।

1953 में, भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया और टाटा संस से एयर लाइन्स में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी, हालांकि इसके संस्थापक जेआरडी टाटा 1977 तक अध्यक्ष के रूप में बने रहे। कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया गया तथा घरेलू सेवाओं को भारतीय एयरलाइंस के पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया।

Q.28) अंगूठे के एक सामान्य नियम के रूप में, 'मंदी' (Recession) को परिभाषित किया गया है

- मंदी दो तिमाही तक जीडीपी की नकारात्मक वृद्धि है।
- जब दो सप्ताह में शेयर बाजार 40% से अधिक गिर जाता है।
- जब देश में बेरोजगारी दर 10% से अधिक होती है
- जब वैश्विक जीडीपी में 10% की गिरावट आती है।

Q.28) Solution (a)

मंदी लगातार दो तिमाहियों के लिए नकारात्मक आर्थिक विकास की अवधि के रूप में विशेषता है। एक मंदी में, बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन में गिरावट और सरकारी उधार में वृद्धि होगी।

Q.29) मानव विकास सूचकांक (HDI) निम्न में से किस आयाम में औसत उपलब्धि को मापता है?

- जीवन प्रत्याशा
- शिक्षा
- प्रति व्यक्ति आय

सही कूट का चयन करें:

- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.29) Solution (d)

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जो मानव विकास के चार स्तरों में देशों को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Q.30) 'मुद्रा वेग' (Velocity of Money) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- यह उस समय की संख्या के रूप में लिया जाता है जब मुद्रा की एक इकाई का उपयोग परिभाषित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है।
- मुद्रा वेग फॉर्मूला, मुद्रा की आपूर्ति द्वारा अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को विभाजित करता है।

सही कथनों का चयन करें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

IASbaba 60 Day Plan 2020 – Day 33 Economics

Q.30) Solution (c)

मुद्रा वेग (velocity of money) वह दर है जिस पर उपभोक्ता और व्यवसाय अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च करते हैं। आम तौर पर, मुद्रा वेग उस समय की संख्या के रूप में लिया जाता है, जब मुद्रा की एक इकाई का उपयोग परिभाषित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है।

मुद्रा वेग का फॉर्मूला, मुद्रा आपूर्ति द्वारा अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को विभाजित करता है, जैसा कि नीचे की गणना में दिखाया गया है:

$$\text{मुद्रा वेग} = \text{जीडीपी} \div \text{मुद्रा आपूर्ति}$$

